नदियों में प्रदूषण का स्तर

81. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नदियों का 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन नदियों का पानी प्रदूषित है;

(घ) नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठा रही है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी-कितनी धन-राशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश के कुल प्रदूषित नदी जल के प्रतिशत के संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) शहरी मलजल के नालों और औद्योगिक विसर्जन के स्थान के नदी के निचले हिस्से प्रायः प्रदूषित होते हैं। शहरी मलजल का अधिकांश अंश बिना शोधन किए अथवा आंशिक रूप से शोधन करके विसर्जित कर दिया जाता है। औद्योगिक बहिस्राव का कुछ भाग भी वांछनीय स्तर तक शोधित नहीं किया जाता है, जिससे नदी जल की-गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, जीवनाशकों, कीटनाशकों तथा उर्वरकों वाले कृषि के बह कर आने वाले जल, धोबी घाट तथा मनुष्यों तथा मवेशियों के स्नान का भी नदी जल में प्रदूषण बढ़ाने में योगदान है।

(ग) नदी जल गुणवत्ता निगरानी आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा के अतिरिक्त अन्य 13 नदियों के अत्यधिक प्रदूषित भागों की शिनाख्त की है। ये नदियां हैं :- साबरमती, यमुना, सुबर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, चम्बल, सतलुज, दामोदर, गोमती, काली, खान, क्षिप्रा और हिंडन।

(घ) नदी जल के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(3) उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण और उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश बनाए गए हैं;

(4) बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है;

(5) नदी प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है;

(6) प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(7) सांझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है;

(8) राज्य सरकारों से परामर्श करके 17 प्रकार के अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समय-बद्ध कार्य योजना तैयार की गई है तथा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत इन श्रेणियों की प्रदूषित इकाइयों के लिए 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करना आवश्यक है;

(9) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई।

(ङ) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल
1.	1985–86	4.61	0.45	1.0
2.	1986–87	15.99	2.48	5.92
3.	1987–88	19.09	6.31	16.43
4.	1988–89	16.54	12.44	25.79
5.	1989–90	22.62	8.80	26.24
6.	1990–91	19.85	6.12	24.39

Privatisation of Railways

82. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Hindustan Times, dated October 16, 1991 captioned, "Privatisation of Railways Mooted";

(b) if so, what are the facts in this regard; and

(c) the steps Government propose to take regarding the re-employment of the large departmental catering staff who are likely to be retrenched if Railway Catering is privatised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Railways are exploring the possibilities of commercial exploitation of railway land. The details of the scheme for privatisation of the existing departmental catering unit have not yet been finalised.

"Ganges now dirty river of sorrow"

83. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ganges has become a polluted river and the people living on its banks are under constant threat of man-made floods, as per the news-item entitled "Ganges now dirty river of sorrow" which appeared in the Hindustan Times, dated October 21, 1991;

(b) If so, whether the Ganga Action Plan has failed to improve quality of water in river Ganges by reducing the pollution load on the river; and